भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5297

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

भारतमाला परियोजना-II

5297. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

डॉ. राजेश मिश्रा:

श्री नव चरण माझी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतमाला परियोजना के द्वितीय चरण के विस्तार की सरकार क्या योजना बना रही है और छत्तीसगढ़ की कितनी सड़कों को इसमें शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस चरण के अंतर्गत एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण से मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को किस प्रकार पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कोई परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं और क्या भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितताओं अथवा भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतमाला परियोजना-II के अंतर्गत कितनी सड़कों को जोड़े जाने का प्रस्ताव है; और

(च) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा भूमि अधिग्रहण की शर्तों के उल्लंघन के कारण राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को कितनी हानि हुई है और क्या इस हानि का कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) एवं (ङ) भारतमाला परियोजना चरण II के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया जाता है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, सरकार ने भूमिराशि पोर्टल विकसित किया है, जो विभिन्न अधिसूचनाओं के तेजी से क्रियान्वयन और लाभार्थियों के खातों में मुआवज़ा राशि के सीधे जमा होने के साथ पारदर्शिता को सक्षम बनाता है, जिससे किसी भी अनियमितता या भ्रष्टाचार की संभावना से बचा जा सके। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकारों के संबंधित मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा समीक्षा सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी की जा रही है।

*****